भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2791

उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026 (बुधवार)

14 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

बाढ़ नियंत्रण के लिए एनईएसआईडीएस और पीएम-डिवाइन

†2791. **मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का बार-बार आने वाली बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूमि, आजीविका और सार्वजनिक अवसंरचना के नुकसान को देखते हुए असम राज्य में बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और नदी तट संरक्षण उपायों को सुदृढ़ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण और नदी तटों की सुरक्षा के लिए एनईएसआईडीएस और पीएम-डिवाइन सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए उक्त राज्य सरकार अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(घ) पूरी की गई, चल रही और विलंबित परियोजनाओं सहित कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता के अनुसार बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी स्कीमें बनाती और लागू करती हैं। केंद्र सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए तकनीकी दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करती है।

केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी उपायों, जल-निकासी व्यवस्था के विकास और समुद्र के कटाव से बचाव आदि जैसे कार्यों के लिए राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य भी शामिल हैं, को मदद देने के

उद्देश्य से केंद्र-प्रायोजित कार्यक्रम "बाढ़ नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" लागू कर रही है।

पिछले पांच वर्षों में असम में बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी परियोजनाओं के लिए असम सरकार को कुल 342.63 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" नामक एक परियोजना को सहायता दी है और यह कार्य 207 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो गया है।

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की स्कीमों के तहत, असम में बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोध और नदी तट संरक्षण उपायों से जुड़ी 6 और परियोजनाओं को 33.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तपोषित किया गया है। सूची **अनुबंध** में संलग्न है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) में पानी की धारणीयता को बढ़ाने तथा बाढ़ और कटाव का खतरा कम करने के लिए उनका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करने हेतु असम में एनईएसएसी द्वारा लगभग 5,900 वर्ग किमी. वेटलैंड्स क्षेत्र को चिन्हित किया गया है और असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा 3,500 से अधिक वेटलैंड्स का प्रलेखीकरण किया गया है।

*****

<u>अनुबंध</u>

"बाढ़ नियंत्रण के लिए एनईएसआईडीएस और पीएम-डिवाइन" विषय पर लोक सभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2791 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनईसी की स्कीमों के तहत, असम में बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और नदी तट संरक्षण उपायों से जुड़ी, सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1.	असम में धेमाजी जिले में जियाधल नदी पर नियंत्रण कार्य, चरण-I	14.94
2.	असम में जनाली नदी के कटाव से रायमोना गांव और उसके निकटवर्ती क्षेत्र का बचाव	3.74
3.	कोकराझार जिले में पेकुआ नदी के कटाव से रानीपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी उपाय।	3.43
4.	पोमरा नदी (असम), बस्का जिले के दोनों किनारों पर अलग-अलग जगहों पर कटाव-रोधी उपाय	2.28
5.	असम के कोकराझार में गंगिया नदी के कटाव से उमा नगर के गांवों और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को बचाने के लिए कटाव-रोधी उपाय	4.05
6.	असम के बक्सा ज़िले में दरंगा नदी के अलग-अलग हिस्सों में नदी के किनारे बीबी को कटाव से बचाने के उपाय।	4.96
	कुल	**33.40**

*****